हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 109 लखनऊ, शुक्रवार 05 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

यूपी में बेरोजगारी दर 19 से घटकर 2.4 प्रतिशत पर, बोले योगी, प्रदेश बना रोजगार का हब

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि पिछले आठ वर्षों में दूरदृष्टि और सशक्त नीतियों की बदौलत राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई पहचान मिली है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं और युवाओं को प्रशिक्षण और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इन सबके साथ सामाजिक स्थिरता और ग्रामीण जीवन में सुधार की स्पष्ट झलक भी देखने को मिल रही है। यह सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व के कारण संभव हो रहा है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बेरोजगारी दर में आई भारी गिरावट है। जहां एक समय प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत जैसे भारी–भरकम स्तर तक पहुंच गई थी, वहीं अब यह घटकर 2.4 प्रतिशत रह गई है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि नीति आधारित विकास मॉडल की सफलता को दर्शाने का काम कर रही है। सरकार द्वारा बनाई गई रोजगार नीतियों, निवेश आकर्षित करने वाले उपायों और कौशल विकास कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की जीसीसी नीति 2025 ने रोजगार वृद्धि को नया आयाम दिया है। इस नीति के माध्यम से दो लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक कंपनियों के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण तैयार करने का जो ठोस प्रयास किया जा रहा उससे युवाओं को तकनीकी और उच्चस्तरीय रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही यूपी रोजगार मिशन ने मात्र एक वर्ष में 1. 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर राज्य में रोजगार सृजन की गति को और अधिक तेज किया है। एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है। प्रदेश में इस समय 96 लाख से

ज्यादा एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनसे अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो चुका है। केवल पिछले एक वर्ष में ही इस क्षेत्र ने 18 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए हैं। यह सेक्टर सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए अवसरों का विशाल प्लेटफॉर्म बन गया है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार भी तैयार कर रहा है। कौशल विकास मिशन ने युवाओं की क्षमता को मार्केट डिमांड के अनुरूप ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिशन के अंतर्गत 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें से 5.66 लाख को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इससे न केवल उद्योगों को स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध हुआ बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को स्थानीय आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। महिला रोजगार में वृद्धि प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक है। आज औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इससे परिवारों की आर्थिक मजबूती जेंडर समानता और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को अभूतपूर्व गतिशीलता प्रदान की है। रोजगार महाकुंभ 2025 जैसे बड़े आयोजन और विभिन्न वित्तीय योजनाओं ने युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर दिए हैं बल्कि उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी मिली है। इससे रोजगार बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता दोनों बढ़ी हैं।

वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, बिहार में शराब तस्करी के लिए कारें चुराने के चार आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी

कानपुर। गोविंदनगर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की पांच कारें बरामद कीं। इनमें से तीन कारें गोविंदनगर थाना क्षेत्र से ही चोरी की गई हैं। शातिर चोरी की कारों को बिहार में बेचते थे जहां इनका इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जाता है। सभी आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बीते कुछ माह में दादानगर फैक्टरी एरिया से तीन कारें चोरी हुई थीं। इनके खुलासे के लिए पुलिस काम कर रही थी। गोविंदनगर इंस्पेक्टर रिकेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने बिहार से नालंदा के हरनौत निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि वह शराब तस्कर है। पटना के थाना कंकड़ बाग के अशोकनगर इलाके के सूरज कुमार और बलिया के नरही के पवन उपाध्याय उर्फ गलगल बाबा संग मिलकर शराब तस्करी करता है। इस काम के लिए उसे चोरी की गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। इन गाड़ियों

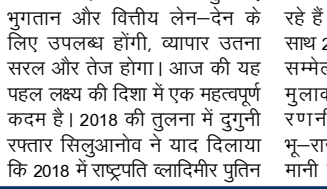

को आशियाना लखनऊ का रहने वाला सत्यम गुप्ता चुराकर उन्हें बेचता है। फिर इन्हीं कारों की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर में हेरफेर कर इनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता है। ऐसे बरामद हुईं स्विफ्ट डिजायर व नेक्सॉन कारें पुलिस ने सबसे पहले राजकुमार को गिरफ्तार किया। राजकुमार से पूछताछ में सत्यम का नाम खुला जो कारें चुराकर उन्हें बेचने का काम करता है। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को सत्यम ने चोरी की तीन कारों की डिलीवरी देने के लिए सूरज और पवन को गोविंदनपुरी के पास बुलाया। यहां पुलिस ने घेराबंदी करके इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी हुई स्विफ्ट डिजायर , सफेद और नीले रंग की नेक्सॉन कारें बरामद कीं। इन वाहनों का सौदा 50 हजार से लेकर चार लाख रुपये तक में हुआ था। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई वैगन आर और ब्रीजा कार भी बरामद की। सौ से ज्यादा कारें चुरा चुका सत्यम इंस्पेक्टर गोविंदनगर रिकेश कुमार ने बताया कि सत्यम बेहद शातिर चोर है। वह चंद सेकेंड में ही कारों के लॉक तोड़कर उन्हें लेकर चंपत हो जाता है। उस पर कानपुर, बलिया, लखनऊ आदि जिलों में कुल 21 मामले दर्ज हैं।

कोडीन कफ सिरप पर सियासत तेज, अखिलेश बोले–प्रदेश में एक जिला...एक माफिया का राज

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय

अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि नशीले सिरप का सिंडिकेट न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होता हुआ नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका तक अपना नेटवर्क चला रहा था। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिरप की वजह से कई मासूमों की जानें गईं, लेकिन शासन–प्रशासन में बैठे प्रभावशाली लोगों की भूमिकाओं की अनदेखी होती रही। अखिलेश ने दावा किया कि इस अवैध धंधे में मुख्यमंत्री के करीबियों और कई अधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि "प्रदेश में एक जिला, एक माफिया का काला कारोबार खुलकर फल–फूल रहा है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही इस मामले में 38 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और स्थानीय माफियाओं के नाम सामने आए हैं। उन्होंने वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व जहरीला सिरप पीने से उनकी मौत हुई, लेकिन उनकी पत्नी द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर और आजमगढ़ में यह धंधा "बड़ों की शह" पर चलता रहा। अखिलेश ने कही ये बड़ी बात कोडीन सिरप मामले में ईडी की एंट्री पर अखिलेश ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि "देश के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता" इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि वाराणसी के पड़ोसी जिले के एक बाहुबली को यह नेता पसंद नहीं करते, इसलिए जैसे ही उसके रिश्तेदारों का नाम आया। केंद्र से दबाव बढ़ गया। आरोप है कि कोडीन सिंडिकेट का सरगना शुभम बाहुबली के रिश्तेदारों के साथ साझेदारी में था और उसने लगभग 84 करोड़ रुपये निवेश किए तथा महंगी गाड़ियां गिफ्ट कीं। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि एक और बाहुबली का शागिर्द भी इस धंधे में करोड़ों लेकर बैठा है और उसे सुरक्षा देने के नाम पर सत्ताधारी नेताओं को महंगे उपहार व मोटी रकम दी जाती थी।

तकनीक और रक्षा में रूस भारत का रणनीतिक साझेदार

रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक में बोले राजनाथ सिंह

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को और गहराई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि रूस अब भी भारत का रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार है, खासकर रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में। रक्षा मंत्री यह बात नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित 22वें भारत–रूस अंतर –सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक में बोल रहे थे, जहां उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलोउसॉव भी मौजूद थे। भू–राजनीतिक बदलावों के बावजूद रिश्ते मजबूत– राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह ने कहा, रूस तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में भारत का रणनीतिक सहयोगी है। भूराजनैतिक बदलावों के बावजूद दोनों देशों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार संवाद में रहे हैं, और यह राजनीतिक स्तर पर विश्वास को और मजबूत

करता है। रक्षा सहयोग, अनुबंध और तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा 22वें आयोग की बैठक में सैन्य उत्पादन, संयुक्त विकास, लाइसेंस प्राप्त मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक हस्तांतरण सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से बातचीत हुई। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसॉव ने त्रि–सेवा गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया और दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कदम राजनाथ सिंह ने बताया कि पिछले महीने मॉस्को में हुई 26वीं भारत–रूस कार्य समूह बैठक सफल रही और यूरोएशियन इकनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा श्यह पहल आने वाले वर्षों में व्यापार और रक्षा, दोनों क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगी। दोनों नेता इससे पहले इस साल सितंबर में तियानजिन, चीन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी में सुखोई, ब्रह्मोस, टी–90 टैंक, और नौसैनिक सहयोग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। रूस और भारत आने वाले वर्षों में व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में हैं। रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने कहा है कि दोनों देश 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक व्यापार लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भरोसा एक साक्षात्कार में रूसी मीडिया से बातचीत के दौरान जताया। सिलुआनोव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में व्यापार की रफ्तार ने उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है और ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय सेवाओं, मशीनरी और यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। वीटीबी बैंक से बढ़ेगा व्यापारिक ढांचा रूसी वित्त मंत्री ने भारत में रूसी सरकारी बैंक वीटीबी के नए फ्लैगशिप कार्यालय के उद्घाटन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, जितनी अधिक सुविधाएं भुगतान और वित्तीय लेन–देन के लिए उपलब्ध होंगी, व्यापार उतना सरल और तेज होगा। आज की यह पहल लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2018 की तुलना में दुगुनी रफ्तार सिलुआनोव ने याद दिलाया कि 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के लिए 30 अरब डॉलर का लक्ष्य तय किया था, लेकिन आज व्यापार 68 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, हमने यह लक्ष्य उम्मीद से कहीं तेज हासिल किया। रक्षा सहयोग, ऊर्जा व्यापार और उद्योगों के बीच बढ़ती साझेदारी ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय आयात बढ़ाने पर जोर सिलुआनोव ने संकेत दिया कि रूस अब भारत से आयात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार, हम भारत से आयात में वृद्धि के लिए कदम उठा रहे हैं। वित्तीय प्रणाली जितनी सरल होगी, निवेश, पर्यटन और व्यापार उतना बढ़ेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें सालाना भारत–रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के लिए रणनीतिक, आर्थिक और भू–राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

कश्मीर में 'चिल्लेकलां' से पहले ही भयानक सर्दी का अंदेशा , खाने–पीने की वस्तुओं की कमी का करना पड़ सकता है सामना

एजेंसी

जम्मू। कश्मीर में चिल्लेकलां (भयानक सर्दी का मौसम) का आगमन अभी 17 दिन दूर है पर कश्मीरी अभी से ठंड से चिल्लाने लगे हैं। ऐसे में उन्हें चिंता है कि इस बार चिल्लेकलां के दौरान कितनी भयानक सर्दी पड़ेगी। हालांकि समय चक्र के सुधार से कश्मीर में पानी की किल्लत और बिजली की कमी जैसी परेशानियों से निजात मिलने की उम्मीद तो जगती है लेकिन कश्मीरी परेशानियों के दौर से गुजरने को मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से मौसम के खराब रहने के कारण राजमार्ग के बार–बार बंद रहने का परिणाम यह होता है कि कश्मीरियों को चिंता इस बात की रहती है कि उन्हें खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी का सामना किसी भी समय करना पड़ सकता है। पहले चिल्लेकलां के शुरू होने से पहले ही कश्मीरी सब्जियों को सुखा कर तथा अन्य चीजों का भंडारण कर लेते थे मगर कई सालों से मौसम चक्र के गड़बड़ रहने के कारण वे इसे भुला बैठे थे।

पुलिस और गोतस्करों में मुठभेड़, तीन को लगी गोली, 26 गोवंश बरामद

एजेंसी

कन्नौज। मैनपुरी से कंटेनर में गोवंश लादकर बिहार जा रहे गोतस्करों की जब पुलिस ने घेराबंदी की तो तीन चकमा देकर भाग गए, जबकि एक को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद तीनों गोतस्करों की बिरौली के जंगल में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में तीन गोतस्करों के पैर में गोली लग गई। तीनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस कंटेनर समेत 26 गोवंश, तीन तमंचे, चार खोखा व तीन जीवित कारतूस बरामद किए हैं। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि मैनपुरी से एक कंटेनर में गोवंशों को लादकर गोतस्कर बिहार जा रहे हैं। पुलिस ने आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर की घेराबंदी की तो तीन गोतस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गए, जबकि गोतस्कर जनपद रामपुर के छोटा काशीपुर गंज निवासी नईम को पकड़ लिया। इसके बाद फरार गोतस्करों की तलाश में एसपी ने एसओजी, सर्विलांस समेत पांच पुलिस टीमों को लगाया। शाम को तालग्राम–तेराजाकेट मार्ग पर बिरौली गांव के जंगल में छिपे गोतस्करों की जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर अंतर्गत मोहल्ला तकिया गुलाबबाड़ी निवासी एहतशाम, इसी कस्बे में मोहल्ला मनिहारन निवासी शमशेर व जनपद मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के शाहजहांपुर निवासी शहजाद के पैर में गोली लग गई। पुलिस कर्मियों ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज

भेज दिया गया। मौके पर एसपी विनोद कुमार, सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय पहुंचे और मुठभेड़ के बारे में जानकारी ली। पुलिस को गोतस्करों के पास से तीन तमंचे, चार खोखा व तीन जीवित कारतूस मिले हैं। चारों तरफ से की गई थी घेराबंदी, शातिर निकले गोतस्कर कंटेनर पकड़े जाने के बाद तीनों गोतस्कर पैदल ही भाग निकले। एसपी ने चारों दिशाओं में उनकी घेराबंदी कराई। उत्तर तरफ गुरसहायगंज कोतवाल अजय अवस्थी, पश्चिम तरफ छिबरामऊ कोतवाल विष्णुकांत तिवारी, दक्षिण तरफ तालग्राम थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह, सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह व पूरब की तरफ एसओजी प्रभारी जयप्रकाश शर्मा व तिर्वा कोतवाल संजय शुक्ला उनकी तलाश में लगे थे। बाद में तीनों के बिरौली के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली तो पुलिस ने चारों दिशाओं से उनकी घेराबंदी कर ली। जब पुलिस टीम जंगल में पहुंची तो गोतस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि शमशेर शातिर है और उसके खिलाफ बनारस व मथुरा में कई मुकदमे दर्ज हैं तो एहतशाम पर हाथरस में भी मुकदमे हैं। पकड़े गए नईम के खिलाफ भी हाथरस जिले में चार मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने पुलिस टीमों को दिया 20 हजार रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि तीनों गोतस्करों को गिरफ्तार करने की वाली टीमों को 20 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है। बरामद गोवंश को गोशाला में भेज दिया गया है और कंटेनर को सीज कर दिया गया। यह कंटेनर शमशेर ने तस्करी के उद्देश्य से ही खरीदा था। सभी गोवंश कटने के लिए बिहार ले जाए जा रहे थे। मथुरा की टीम कर रही थी गोतस्करों का पीछा जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन निवासी श्रेयस ने बताया कि उनकी टीम मैनपुरी से गोतस्करों का पीछा कर रही थी। उनके साथ शिशिर, रामबाबू, लक्ष्मण सिंह, नितिन व सुमित भी थे। एक्सप्रेसवे पर कई जगह कंटेनर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। जब उन्होंने पीछा किया को चालक ने कंटेनर को रान्ग साइड पर मोड़ दिया और डिवाइडर फांदकर दूसरी लेन पर ले गया। कंटेनर के साथ एक स्विफ्ट कार भी चल रही थी, जिसमें उनका साथ मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर अंतर्गत पद्दा वाला तालाब छलिया निवासी अनस सवार था। नईम को इन्हीं युवकों ने पकड़ लिया था।

सोशल मीडिया अकाउंट खंगालकर कर अमेरिका दे रहा वीजा, सख्त नियमों पर जयशंकर बोले- ये उनका अधिकार

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा वीजा नियमों को और कड़ा किए जाने पर भारत ने स्पष्ट किया है कि वीजा जारी करना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका हर वीज़ा आवेदन को अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है और यह उसका अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के आधार पर निर्णय ले। अमेरिकी कदमों से भारतीय छात्रों और पेशेवरों की बढ़ती चिंताओं के बीच भारत सरकार ने यह प्रतिक्रिया दी है। जयशंकर ने बताया कि अमेरिका ने हाल में किए गए बदलावों के तहत वीज़ा जांच को पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। अब छात्र वीजा ही नहीं, बल्कि एच–1ठ और एच–4 आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट भी पूरी तरह सार्वजनिक रखने होंगे ताकि उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की गहन जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह नई नीति भारतीय छात्रों, पेशेवरों और वीजा आवेदकों को सीधे प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया जांच अनिवार्य अमेरिका ने निर्देश दिया है कि 15 दिसंबर से सभी H–1B और H–4 आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक होने चाहिए ताकि वीज़ा अधिकारी उनका पूरा ऑनलाइन इतिहास देख सकें। इससे पहले यह नियम छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर लागू था, जिसे अब और व्यापक कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि वीज़ा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक प्रिविलेज है और देश की सुरक्षा के लिए सभी डिजिटल गतिविधियों की जांच जरूरी है। छात्रों की समस्याओं पर भारत की चिंता विदेश मंत्री ने बताया कि अप्रैल 2025 में अमेरिका की नई नीति लागू होने के बाद कई छात्रों के वीज़े मामूली कारणों से रद्द कर दिए गए। कई मामलों में छात्रों पर स्वयं देश छोड़ने का दबाव भी बनाया गया। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ऐसे हर मामले में दूतावास और वाणिज्य दूतावास के जरिए दखल दे रही है और अमेरिका को बताया गया है कि छोटे अपराधों या तकनीकी गलतियों पर सख्त कार्रवाई उचित नहीं है। वीजा प्रक्रिया में सख्ती बढ़ाने का तर्क अमेरिका ने कहा है कि उसके लिए हर वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन लगातार वीज़ा और इमिग्रेशन नियमों को कड़ा कर रहा है। उनका दावा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, सभी आवेदकों को अपनी पात्रता साबित करनी होगी और यह भरोसा देना होगा कि वे वीजा नियमों का पालन करेंगे। भारत की स्थिति और आगे की कार्रवाई जयशंकर ने कहा कि भारत कई मामलों में अमेरिका से बात कर चुका है।

संपादकीय

साथी पर अविश्वास

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि आगामी वर्ष मार्च से हर नये स्मार्टफोन में 'संचार साथी' ऐप पहले इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर पुराने स्मार्ट फोनों में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा भेजा जाएगा। जिसको लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना था कि इससे निजता का उल्लंघन होगा और व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री–इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल, सरकार का कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप से नई तरह की असुरक्षा पैदा हो सकती है। बताया जाता है कि सरकार ने स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप इस तरह इंस्टाल करने को कहा था ताकि उसे डिलीट या अक्षम न किया जा सके। केंद्र की दलील थी कि यह ऐप उपभोक्ता को धोखाधड़ी वाले फोन और संदेशों की रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता। साथ ही चोरी किए गए मोबाइल की बरामदगी आसान हो पाती। लेकिन निजी डेटा सुरक्षा व इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। वैसे सर्च इंजन में पहले से मौजूद इस ऐप को देश के लाखों लोग पहले ही स्वेच्छा से डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इसको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश के बाद विरोध के स्वर उभरने लगे। जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिये व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करके उसके जीवन में ताक–झांक की जा सकती है।

हालांकि, विरोध के सुर मुखर होने के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि यह निर्णय वैकल्पिक है और कोई व्यक्ति इस ऐप को इच्छानुसार डिलीट कर सकता है। निस्संदेह, निजता हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी ऐप की अनिवार्यता से व्यक्ति की गोपनीयता में खलल पड़ने की आशंका जतायी जाने लगी। पिछले दिनों सरकार ने व्हाट्स ऐप व टेलीग्राम आदि कम्युनिकेशन ऐप्स संचालक कंपनियों से कहा था कि वे अपनी सेवा को मोबाइल के सिम कार्ड से जोड़कर रखें। ताकि सिम के बिना इन ऐप का दुरुपयोग न हो सके। जिसको लेकर टेलि–कम्युनिकेशन कंपनियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया था। निस्संदेह, निजता का अधिकार देश में मौलिक अधिकार के रूप में मौजूद है। शीर्ष अदालत ने भी अपने एक निर्णय के जरिये स्पष्ट किया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में 'राइट टू प्राइवेसी' में भी निहित है। जिसके अंतर्गत मोबाइल, इंटरनेट व डिजिटल जानकारियां भी शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से इतर व्यक्ति को अपनी डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा का हक है। यही वजह है कि विगत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोबाइल व निजी कंपनियां उपभोक्ता से आधार कार्ड नहीं मांग सकती। इस फैसले को तब निजता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। यही वजह है कि 'संचार साथी' की अनिवार्यता के बाद निजता व व्यक्ति के डेटा में सरकारी दखल को लेकर सवाल उठने लगे। निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो सेंध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके।'

राशिफल

मेष :– जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है। नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का एहसास होगा। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

बृषभ :– शासन–सत्ता से जुड़े लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य पूर्ण होने के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा।

मिथुन :– संबंधों में व्यवहार कुशल बने। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागेदारी संभव। निकट संबंधों में अपनी अच्छी छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता से उत्साहित होंगे।

कर्क :– विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होंगी। नवीन आशाएं नये उत्साह का संचार करेंगी। कार्यक्षेत्र में संबंधों का भरपूर लाभ उठाएंगे।

सिंह :– अंतमरुखी स्वभाव को त्याग बाह्यमुखी बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली रहेगी।

कन्या :– पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे। शिक्षा में समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन नकारात्मक चिंताओं से बोझिल होगा।

तुला:– किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। पारिवारिक वातावरण में उत्साह का माहौल रहेगा। दुबिधाओं का त्याग कर लक्ष्य पर केंद्रित हों।

वृश्चिक :– कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में ब्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों के भावनात्मक सहयोग से मन उत्साहित होगा। हंसमुख स्वभाव से आसपास का माहौल प्रसन्न होगा।

धनु :– कठिन एवं विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा में बढ़ेगी। घरेलू दायित्वों की पूर्ति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

मकर :– कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। निकट संबंधों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। गैर सांस्कारिक कायरे की आकर्षित मन पर अंकुश लगायें।

कुंभ :– कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत् क्षेत्रों में संघर्ष संभव परंतु निराशावादी विचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ऊर्जा की अनुभूति होगी। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

मीन :– नकारात्मक चिंताओ को त्याग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरी–पेशे में अधिकारियो व सहकर्मियो के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा।

जवाबदेही की नई राह : मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट और सदन अध्यक्ष द्वारा समीक्षा

लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत समीक्षा की नई पहल

–डॉ सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र की सफलता केवल जनता की भागीदारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इससे भी अधिक इस बात पर आधारित होती है कि शासन–तंत्र कितना जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुख है। भारत जैसे विशाल और बहुस्तरीय लोकतंत्र में यह प्रश्न कई गुना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मंत्रीकृजो विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष प्रशासक हैं–अपने विभाग के कार्य, नीतियों और दैनिक प्रशासनिक निर्णयों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं? समय–समय पर यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि शासन में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और नीतिगत अस्पष्टता जैसी समस्याएँ निर्णय–प्रक्रिया को कमजोर करती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में यह विचार उभरता है कि मंत्रियों के कार्य–काज की नियमित रिपोर्ट तैयार की जाए और उसकी समीक्षा सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाए। यह प्रस्ताव मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति–संतुलन, नैतिक जिम्मेदारी और जन–विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। भारत की संवैधानिक संरचना में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका के रूप में मंत्री शासन–व्यवस्था की धुरी होते हैं, परंतु उनकी जवाबदेही अक्सर केवल चुनावी परिणामों या राजनीतिक आलोचनाओं तक सीमित रह जाती है। यदि इनके दायित्वों और निर्णयों का नियमित आकलन एक संस्थागत प्रक्रिया के अंतर्गत हो, तो शासन न केवल अधिक पारदर्शी होगा बल्कि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी भी बन सकेगा। मंत्रियों की कार्य–रिपोर्ट तैयार करने का विचार शासन के उस बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है, जिसमें कार्यपालिका को अपनी प्रत्येक गतिविधि का तर्कसंगत विवरण देना होता है। एक व्यवस्थित रिपोर्ट मंत्री को बाध्य करती है कि वह अपने विभाग की वास्तविक स्थिति, योजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपयोग, चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों को सत्य और स्पष्ट रूप में वर्णित करे। यह दस्तावेज़ किसी राजनीतिक भाषण या प्रचार की तरह नहीं, बल्कि शासन का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड बनता है। यदि इस रिपोर्ट की समीक्षा सदन अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो इसकी विश्वसनीयता और गंभीरता दोनों ही बढ़ जाती हैं। सदन अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में तटस्थता के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनकी भूमिका केवल सदन की कार्यवाही का संचालन करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे विधायी नैतिकता और संसदीय मर्यादाओं के संरक्षक भी होते हैं। उनकी समीक्षा एक निष्पक्ष, संतुलित और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी प्रणाली मंत्री की स्वतंत्रता को सीमित कर देगी। परंतु यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसी भी पद की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है, उससे अलग नहीं होती। जब एक मंत्री जानता है कि उसके प्रत्येक निर्णय का औपचारिक दस्तावेज़ बनकर समीक्षा के लिए जाएगा, तो वह नीतिगत गंभीरता और प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत रूप से अपनाता है। इसके साथ ही, एक ऐसी रिपोर्टिंग व्यवस्था शासन में निरंतरता भी सुनिश्चित करती है। मंत्रालयों में मंत्रियों का परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अक्सर नीतियाँ इसी संक्रमण में कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि नई नेतृत्व टीम को पिछली प्रगति की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। नियमित रिपोर्टें इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं। इससे शासन में न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में मंत्रियों की नियमित रिपोर्ट संसद या उसकी समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि जवाबदेही केवल राजनीतिक आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि शासन का एक अनिवार्य अंग है। भारत में यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो यह वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता का अधिकार है। भारत में नागरिक बार–बार यह भावना व्यक्त करते हैं कि शासन–तंत्र उनके प्रति पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है। योजनाओं की प्रगति, बजट का वास्तविक उपयोग और समय–सीमाएँ अक्सर अस्पष्ट रहती हैं। इस प्रस्ताव के लागू होने से जनता को भी मंत्रालयों के कार्य–काज का प्रामाणिक सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद स्थापित होगा। सदन अध्यक्ष द्वारा की गई समीक्षा आलोचना का रूप नहीं होगी; यह सुधारात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगी। समीक्षा से मिली टिप्पणियाँ मंत्री के लिए दिशानिर्देश बन सकती हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता और नीतियों की गुणवत्ता को और ऊँचा उठाने में मदद करेंगी। जब तंत्र निष्पक्ष निगरानी के साथ चलता है, तो लापरवाही और विलंब जैसी समस्याएँ स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह प्रस्ताव शासन की उस बुनियादी धारणा को फिर से स्थापित करता है कि सत्ता का उद्देश्य केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। मंत्री जब अपने दायित्वों का नियमित लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं, तो वे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता में योगदान देते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता को भी मजबूत करते हैं। निष्कर्षतः, मंत्रियों की कार्य–रिपोर्ट और सदन अध्यक्ष द्वारा उसकी समीक्षा एक ऐसी पहल है जो भारत के लोकतंत्र को अधिक जीवंत, अधिक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बना सकती है। यह प्रस्ताव शासन के प्रत्येक स्तर को उत्तरदायित्व के नए मानदंडों के तहत लाने की क्षमता रखता है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह लोकतंत्र की वास्तविक भावनाकृजन–उत्तरदायित्व, सच्ची सेवा और पारदर्शी शासनकृको और मज़बूत करेगा। ऐसी प्रत्येक पहल लोकतंत्र को सिर्फ़ एक शासन–व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत और मूल्य–आधारित परंपरा बनाती है, जो समय के साथ और भी परिष्कृत होती जाती है।

नए भारत को सुरक्षा एवं संवेदना वाली नई पुलिस चाहिए

–ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था कानून–व्यवस्था की आधारभूत धुरी है, परंतु आम नागरिक के मानस में पुलिस की छवि अभी भी कठोरता, डर और दमन से जुड़ी हुई है। इसे केवल अधिकार जताने वाली शक्ति समझा गया है, संवेदनशीलता, जवाबदेही और मित्र भाव से नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में इसी जटिलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस की छवि तभी बदलेगी जब व्यवस्था अधिक प्रोफेशनल, अधिक उत्तरदायी और अधिक मानवीय बने। विकसित भारत की दृष्टि में पुलिस का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज में भरोसे को पुनर्जीवित करने का कार्य भी है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, आतंकवाद–निरोध, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, चुनाव ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा जैसी असंख्य जिम्मेदारियां हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं, कार्य–भार भारी और राजनीतिक दबाव व्यापक हैं। कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट या कठोर व्यवहार ने संपूर्ण पुलिस व्यवस्था की छवि पर चोट पहुंचाई है, इसलिए जनता पुलिस के निकट आने पर भी भय का अनुभव करती है। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति बदलने की स्पष्ट आवश्यकता जताई और युवाओं में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर बल दिया ताकि आने वाली पीढ़ी पुलिस को मित्र और संरक्षणकर्ता के रूप में पहचाने। भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। वह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून–व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक है। परंतु विडम्बना यह है कि आम जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। समाज पुलिस को "डंडे" और "खाकी" के प्रतीक रूप में पहचानता है, संवेदनशीलता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से नहीं। यही कारण है कि पुलिस सुधार दशकों से विमर्श का विषय तो रहा, लेकिन कभी जनांदोलन नहीं बन सका, न चुनावी मुद्दा बना और न ही गंभीर राजनीतिक प्राथमिकता। इसलिये मोदी ने शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने, विश्वविद्यालयों को फोरेंसिक अध्ययन के लिए प्रेरित करने और नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा संहिता पर व्यापक जनजागरूकता चलाने की जरूरत रेखांकित की। उनका यह दृष्टिकोण पुलिस को प्रतिक्रियाशील संस्था से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमान आधारित और विश्वसनीय संस्था बनाने की दिशा है। प्रधानमंत्री की दृष्टि का महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली मशीन नहीं बल्कि समाज का सहभागी तंत्र है। यदि पुलिस व्यवहार में संवेदनशीलता, संवाद, पारदर्शिता और विनम्रता विकसित करे तो जनविश्वास स्वतः बढ़ेगा। नए कानूनों के बारे में जन–जागरूकता अभियान इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब जनता उन्हें समझती और स्वीकार करती है। अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, इंटेलिजेंस नेटवर्क और फोरेंसिक क्षमता मजबूत होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने नेटग्रिड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटाबेस के प्रभावी उपयोग पर जोर देकर पुलिसिंग को डेटा आधारित, कृत्रिम बुद्धिमता–एआई और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने की दिशा दिखाई है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठनों की सतत निगरानी, नशीली दवाओं के विरुद्ध बहुस्तरीय रणनीति, कट्टरपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में विकास आधारित समाधान, तटीय सुरक्षा के नवाचार, तथा प्राकृतिक आपदाओं में सक्रिय पुलिस नेतृत्व की आवश्यकता भी व्यक्त की। यह सब उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें पुलिस केवल अपराध से लड़ने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि विकास की रणनीतिक सहभागी शक्ति है। परंतु पुलिस सुधार केवल निर्देशों से संभव नहीं; इसके लिए संतुलित एवं अत्याधुनिक ढांचे की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन, मनोबल, आचार–नीति, राजनीतिक निर्भरताओं से मुक्ति और सामाजिक सम्मान शामिल हों। आलोचना जितनी महत्वपूर्ण है, पुलिस के संघर्षों को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसी दोतरफा समझ से सुधार का रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि पुलिस नेतृत्व खुद को नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करे, लक्ष्य स्पष्ट करे और वह व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिक पुलिस को भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखें। विकसित भारत की यात्रा में सुरक्षा, न्यायबोध और अनुशासन की संरचना को सशक्त बनाने के लिए पुलिस का आधुनिक, मानवीय और विश्वसनीय स्वरूप अनिवार्य है। यह सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और चरित्र का परिवर्तन है। तभी खाकी का सम्मान लौटेगा, जनता का विश्वास मजबूत होगा और पुलिस व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में पहचानी जाएगी। प्रधानमंत्री के ताजा विचारों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की छवि सुधारने का अर्थ केवल कठोरता घटाना नहीं, बल्कि उसे प्रोफेशनल, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस व्यवस्था के लिए भय का नहीं, विश्वास और सुरक्षा का केंद्र बने। शहरी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, पर्यटक पुलिस को पुनर्जीवित करने और नए आपराधिक कानूनों पर जन–जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पुलिस "डंडे की ताकत" से आगे बढ़कर "मदद की शक्ति" बनेगी। यदि नागरिक को यह अनुभव होने लगे कि पुलिस मदद के लिए तत्पर है, उसके अधिकारों का सम्मान करती है और कानून का निष्पक्ष पालन करती है, तो खाकी वर्दी का अर्थ केवल अनुशासन नहीं बल्कि विश्वास, अभय और सहारा प्रतीत होगा। यही वह परिवर्तन है जो विकसित भारत की सोच में निहित है। अंग्रेज़ी शासकों ने अपने शासन को थोपने, जनता को नियंत्रित करने और भय–आधारित प्रशासन चलाने हेतु पुलिस तंत्र की रचना की। 1860 के कानून के आधार पर स्थापित भारतीय पुलिस का मूल चरित्र दंडात्मक, शासक–केन्द्रित और कठोर शक्ति–प्रयोग वाला था। स्वतंत्रता के बाद भी इस व्यवस्था में सार्थक बदलाव न होना एक विडंबना है। आज़ाद भारत ने लोकतंत्र अपनाया पर पुलिस ढांचे ने अभी तक औपनिवेशिक सोच को पूरी तरह त्यागा नहीं। परिणामतः पुलिस जनसेवा की बजाय सत्ता को बचाने और भय पैदा करने का उपकरण बनी रह गई। आज आवश्यकता है कि भारत का पुलिस तंत्र भारत के मूल्यों के अनुरूप पुनर्निर्मित हो। विकसित भारत को विकसित सोच वाली पुलिस चाहिए जो नागरिकों के साथ विश्वास–आधारित संबंध बनाए, दमन नहीं बल्कि संरक्षण दे, और कानून को लागू करने में नैतिकता, पारदर्शिता और मानवता को प्राथमिकता दे। ऐसी पुलिस व्यवस्था ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की प्रहरी बन सकती है और भारत की सभ्यता–संस्कारों का प्रतिबिंब भी। इसी संदर्भ में पुलिस थानों के नामकरण की सोच पर पुनर्विचार भी आवश्यक है। "थाना" शब्द में दमन और भय की छाया रही है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में वह नागरिक सहारा का स्थान होना चाहिए। यदि उन्हें "सुरक्षा केंद्र", "नागरिक सहायता केंद्र", "पुलिस सेवा भवन", "अभय केंद्र" या "सहयोग प्रहरी केंद्र" जैसे नाम दिए जाएं तो नागरिक के मानस में पुलिस की भूमिका का अर्थ बदलने लगेगा। नाम केवल शब्द नहीं होता, वह भाव, चरित्र और अनुभव निर्मित करता है। इस सकारात्मक नामकरण से पुलिस केन्द्र केवल शिकायत या धमकाने का प्रतीक नहीं बल्कि सहायता, समस्या–समाधान, विश्वास और न्याय का केन्द्र बन सकता है। यह प्रतीकात्मक परिवर्तन, यदि व्यवहार सुधार के साथ जुड़ जाए, तो पुलिस के प्रति जनता में सम्मान, निर्भयता और साझेदारी की भावना और अधिक मजबूत होगी और यही वह दिशा है जिसे विकसित भारत की सुरक्षा, नीतिगत सोच और संवेदनशील शासन का स्वरूप कह सकते हैं। इसके विपरीत आज की वास्तविकता यह है कि जब पुलिस दरवाजे पर आती है, तो नागरिक घबराता है–"कहीं फंस न जाऊं।" यह भय उस विश्वासहीनता का परिणाम है जिसे बदलना आवश्यक है। अपराध की प्रकृति बदल रही है, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग नेटवर्क–इनसे मुकाबले के लिए बेहतर प्रशिक्षण, तकनीक और इंटेलिजेंस चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस सबसे प्रत्यक्ष शासन–कर्म है। जनता रोज उसे देखती, झेलती और समझती है। खराब अनुभव सीधे शासन के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं।

सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में खुलेंगे रोजगार के असंख्य द्वार

दुनियाभर में सेमीकंडक्टर उद्योग में रोजगार की असीम सम्भावनाएं हैं। फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, 5जी नेटवर्क और एआई आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजिटल तकनीकों में चिप चाहिये। भारत में फैब यूनिट्स शुरू होते ही लाखों नौकरियां आएंगी और स्किल्ड पेशेवरों की मांग होगी। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी., केमिकल इंजी., क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजी., पैकेजिंग विशेषज्ञ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजी. व टेस्टिंग विशेषज्ञों की जरूरत होगी। सेमीकंडक्टर चिप डिजिटल युग की रीढ़ है और प्रत्येक तकनीक की आत्मा बन चुकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, चिकित्सा आधारित मशीनें, इलेक्ट्रिक वाहन, 5जी नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी के केंद्र में यही सूक्ष्म चिप काम करती है। दुनिया भर में चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। युवाओं के पास उच्च वेतन, स्थायी कैरियर और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने का समय है। भारत आज लगभग 90 प्रतिशत चिप आयात करता है। जैसे–जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण बढ़ रहा है, भारत में फैब, असेम्बलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग और डिजाइन कंपनियों की तेजी से स्थापना हो रही है। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्कीम और 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी जैसी नीतियों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति दी है। आने वाले पांच से सात वर्षों में भारत में अनेक फैब और असेम्बलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग यूनिट्स शुरू होने जा रही हैं। एक अकेला फेब्रिकेशन प्लांट 12,000–15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 25,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। अनुमान है कि 2030 तक इस उद्योग में 25–30 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगी। इसके संदर्भ को समझें तो निकट भविष्य में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग विशेषज्ञ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजीनियर, क्वालिटी और टेस्टिंग विशेषज्ञ की बड़े स्तर पर आवश्यकता होगी। सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करने के लिए केवल पारंपरिक इंजीनियरिंग डिग्री पर्याप्त नहीं है। यहां विशेषज्ञता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्लीन रूम आधारित प्रैक्टिकल स्किल्स की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को देखते हुए आईआईटी, एनआईटी और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान इनसे संबंधित कोर्स शुरू कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कोर्स काफी महत्वपूर्ण है। इसमें नैनोफैब्रिकेशन, फोटोलिथोग्राफी, ऑक्सीडेशन, डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन जैसी प्रोसेस सिखाई जाती है। इसी तरह सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कोर्स सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जहां चिप्स को पैक, टेस्ट और मार्क किया जाता है। इसके लिए युवा वायर बॉन्डिंग, फिलप–चिप पैकेजिंग, लेजर कटिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग उपकरण का संचालन सीख कर अपना कैरियर बना सकते हैं। क्लीन रूम ऑपरेशन और मेंटेनेंस का फील्ड रोजगार के लिए काफी उपयुक्त है। सेमीकंडक्टर फैब में धूल का एक कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए प्रशिक्षित क्लीन रूम तकनीशियन की भारी मांग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जो युवा चिप डिजाइन में रुचि रखते हैं, उनके लिए वीएलएसआई, डिजिटल सर्किट डिजाइन, कैड टूल्स जैसे क्षेत्र सर्वोत्तम हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर एसआईसी और जीएएन कोर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। भविष्य ईवी और हाई पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग कई गुना बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर उद्योग में न केवल रोजगार की असीम सम्भावनाएं हैं, बल्कि शुरुआती वेतन भी काफी अच्छा रहता है। प्रारम्भिक वेतन 5 से 12 लाख वार्षिक तक होता है। भारत में फैब यूनिट्स शुरू होते ही लाखों नौकरियां आएंगी और कुशल लोगों को हाथोंहाथ लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह उद्योग दशकों तक लगातार बढ़ने वाला है। भारत में तो अवसरों की भरमार होगी ही, साथ ही ताइवान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में भी काम करने के अवसर मिल सकते हैं। टेस्टिंग, सेंसर और उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप की संभावनाओं को भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता। इस क्षेत्र में उद्यमशीलता सोने पर सुहागा सिद्ध हो सकती है। इसके लिए नैनोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग में अपना आधार मजबूत करें। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग या फैब्रिकेशन से जुड़े स्किल कोर्स करें।

संस्कृति समाप्त हो जाए तो पहचान को खो देता है राष्ट्र : सीएम योगी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह–2025 के शुभारंभ अवसर पर कहा कि जब भी हम संकट में होते हैं या कोई राष्ट्रीय चुनौती होती है तो महापुरुषों के चित्र, उनके शौर्य व पराक्रम नई ऊर्जा देते हैं। राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता व पहचान को खो देता है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई समेत सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले भारत मां के बहादुर जवान देश के लिए प्रेरणा हैं। सीएम योगी ने कहा कि संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है, जिन्हें समय–समय पर अलग–अलग युगांतकारी घटनाओं ने संबल और शक्ति दी। जिन्हें विभिन्न पर्वों के माध्यम से पूरा भारत बिना भेदभाव के आत्मसात करता है। पर्व में मतभेदों को समाप्त करके हम 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण, अपनी संकल्पना और भावना को बढ़ाने के लिए संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। योगी ने कहा कि परिषद शिक्षा के विजन के साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप पॉलीटेक्निक आदि के जरिए तकनीक पर जोर दे रहा है तो वहीं महिलाओं की शिक्षा, अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण के लिए महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र या अन्न संस्थाएं दूरदराज के क्षेत्रों में नए प्रयास को बढ़ाने के साथ ही कार्य कर रही हैं।

कफ सिरप घोटालाः यूपी में सियासी तूफान, संसद तक गूंज

जिन्होंने अपने बच्चे खोये, उनकी पीड़ा कौन समझेगा–धर्मेंद्र यादव

संवाददाता

लखनऊ। यूपी की राजनीति में इन दिनों कथित कफ सिरप घोटाले को लेकर उथल–पुथल है। नकली कफ सिरप से बच्चों की मौतों का मामला राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मामले को उठाया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।बोले, कथित नकली कफ सिरप का इतना बड़ा रैकेट सक्रिय है, जिसकी सप्लाई यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से होते बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका तक पहुंच रही है। सांसद के मुताबिक कथित जहरीली दवा ने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली लेकिन रैकेट में शामिल लोग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर रहे हैं। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनकी पीड़ा को आखिर कौन समझेगा? इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का मॉडल चल रहा है और कफ सिरप व दवा घोटाला हजारों करोड़ का रूप ले चुका है। उनकी सरकार के दौरान दवाओं की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रहती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में हालात बिगड़ते चले गए और पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था तक प्रभावित हुई। अखिलेश ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि बच्चों की जान से जुड़ा मुद्दा है, इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए।

सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, पुलिस कर रही शिनाख्त

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह पारा थाना क्षेत्र के पुराना पारा मोड़ पर एक बुजुर्ग को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े देखा। उनको चोट लगी थी। शायद किसी वाहन ने टक्कर मारी होगी। यह देखकर पुलिस को सूचना दी गई। आसपास के लोगों की मदद से बुजुर्ग को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया।

मदनी और सपा सांसद की सोच एक जैसी, मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार

संवाददाता

लखनऊ। जमीयत–उलेमा–हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के जिहाद पर दिए बयान को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी मदनी के बयान का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को इस पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज ऐजेंसी से बात करते हुए कहा, मदनी, सपा सांसद और समाजवादी पार्टी की सोच एक जैसी है। भारत में अब कोई जिहाद की धमकी न दे। देश में तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देते हुए कानून का राज चल रहा है। उन्होंने कहा, जो लोग जिहाद की धमकी देने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जिहाद की धमकी का जवाब देश की जनता देना जानती है। जब चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी और मदनी जैसे बयान के समर्थन में खड़ी होने वाली पार्टियों को जनता जवाब देगी। केशव प्रसाद मौर्य ने घुसपैठियों को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश, देश का कोई राज्य, या भारत हो, घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है। घुसपैठियों का पता लगाया जाना चाहिए और वे देश से आए हैं, उन्हें वहां पर वापस भेजना चाहिए।

सुजीत लेंगे सुधाकर सिंह की जगह!

अखिलेश और शिवपाल की पसंद हैं सुजीत, लोगो की सहानुभूति भी है साथ

2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बन सकता है घोसी का उपचुनाव

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से घोसी विधानसभा सीट चर्चा में है। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है और जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से सपा के दिग्गज नेता रहे सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। चर्चा की वजह है सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का हालिया बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 13वीं के मौके पर सुधाकर सिंह के घर पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जब अखिलेश यादव से सुजीत सिंह की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो कहा कि पार्टी में इसपर बात की जाएगी। हम सुजीत को आगे बढ़ाएंगे।शिवपाल यादव ने भी माफिक जवाब दिया था। सुजीत सिंह राजनीति में काफी सक्रिय हैं। वह मेधावी छात्र रहे हैं।सुजीत सिंह दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। क्षेत्र में उनकी सक्रियता रहती है। 2013 में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे से एमबीए की डिग्री हासिल की। बैच के टॉपर रहने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए थे। 2015 में लखनऊ के शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। सुजीत सिंह की उम्मीदवारी की चर्चा 2023 के उपचुनाव के दौरान थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला.। 2023 का उपचुनाव बहुत ही फंसा हुआ था और 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता थे।तब अखिलेश यादव ने पीडीए यानि बपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकनका नारा दिया था और बीजेपी से बागी होकर आए सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया जिन्होंने सपा को बड़ी जीत दिलाई। सुधाकर सिंह और अखिलेश यादव के बीच पारिवारिक रिश्ता रहा है। सुधाकर सिंह के निधन के बाद अस्पताल में सुजीत सिंह अखिलेश यादव के गले लगकर रोते दिखे। सुजीत सिंह ने अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि वे परिवार के मुखिया के रूप में आशीर्वाद देने आए थे। घोसी में फिर से उपचुनाव की संभावना है तो यह माना जा रहा है कि यह चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बन सकता है।

लखनऊ में 9000 गाड़ियों की आरसी सस्पेंड

जो चालान नही भरेगा, वो भुगतेगा

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ चालान काटने पर ही नहीं, बल्कि चालान न भरने वालों पर सीधा शिकंजा कस दिया है। परिवहन विभाग ने एक ही आदेश में लगभग 9000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है।इन वाहनों में वे दो स्कूटी भी हैं, जिन पर 200 से ज्यादा चालान हैं।आरसी सस्पेंशन के बाद न इंश्योरेंस हो सकता है न सर्विस बुक अपडेट होगी और न वाहन की बिक् सकेगा। यह गाड़ियां सड़क पर दिखीं तो सीज कर दी जायेगी।ट्रैफिक विभाग की जांच में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।2 स्कूटी ऐसी निकलीं, जिन पर 200 से अधिक चालान पेंडिंग थे।435 वाहन ऐसे हैं जिन पर 50 से ज्यादा चालान दर्ज हैं। पुलिस ने 13,800 ऐसे वाहनों की लिस्ट बनाई है जिन पर 10 या उससे ज्यादा चालान बकाया थे। पहले चरण में 9000 वाहनों की आरसी निलंबित की है, अन्य जिलों की लिस्ट उनके आरटीओ को भेज दी गई है। अभियान का पूरे यूपी में असर दिखने वाला है। एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह के मुताबिक मालिकों को सलाह है कि जुर्माना भर दे क्योंकि जुर्माना भरते ही आरसी स्वतः बहाल हो जाएगी। वाहन मालिकों को तुरंत परिवहन ऐप पर जाकर अपना वाहन नंबर डालकर चालान की स्थिति की जांच करनी चाहिए।बिना हेलमेट 10 बार तक पकड़े जाना,बार–बार बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना,ओवर स्पीड, रेड लाइट जंप, गलत साइड ड्राइविंग और नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना जैसे दोहराए जाने वाले अपराध सीधे आरसी निलंबन का कारण बन रहे हैं।

लखनऊ में नागरिकता जाँच से मचा हड़कंप

160 सफाईकर्मी भागे, मेयर का एनआरसी जाँच का ऐलान

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के नेतृत्व में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू होते ही लखनऊ नगर निगम से जुड़ी कूड़ा प्रबंधन कंपनी के 160 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ भागे। इन कर्मचारियों से नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज मांगे गए थे, जिसके बाद ये सभी काम से गायब हो गए। महापौर ने आशंका व्यक्त की कि ये भागे लोग संदिग्ध रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं।उन्होंने अधिकारियों को तत्काल जांच और आधार के साथ एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर चेक करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये कर्मचारी खुद को असम का बताते थे। ये संदिग्ध दिन में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे और रात में वारदातों को अंजाम दे सकते थे, जैसा कि पिछले साल एक मामले में छह रोहिंग्या पकड़े गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घुसपैठियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश के बाद, मेयर सुषमा खर्कवाल गुरुवार को तुरंत एक्शन मोड में आ गईं।उन्होंने लखनऊ में अवैध ढंग से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तत्काल जांच कर उचित कदम उठाएं। उन्होंने शहर के आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है।लखनऊ में अवैध रूप से बसी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की नागरिकता पड़ताल के लिए जांच अभियान चल रहा है।मेयर ने स्वयं गुडंबा थाने के पास मौके पर जाकर जांच–पड़ताल की। आशंका है कि लखनऊ में एक बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं।

संक्षिप्त

एलयू में स्टूडेंट्स का हंगामा,कैंपस गेट पर मंत्री संजय निषाद का पुतला फूंका

संवाददाता

लखनऊ। मत्स्य मंत्री संजय निषाद के बलिया पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। एलयू के छात्रों ने कैंपस के मुख्य गेट के बाहर उनका पुतला फूंक कर विरोध जताया। छात्र आदित्य पांडे ने कहा बयान बेहूदा और अपमानजनक है। हमारी मांग है कि संजय निषाद को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल बताया था। इस बयान पर शहीद पंडित रामदहीन ओझा के परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़, 13,812 बोतल विदेशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13,812 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एक दिन पूर्व तीन दिसंबर की देर रात लखनऊ में टोल प्लाजा सीतापुर रोड पर की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरील कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से भारी मात्रा में शराब के साथ एक आयशर ट्रक , 5700 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन, डीजल और बोरी भी बरामद की गई। बरामद शराब में रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट की 2052 बोतलें, ओल्ड हैबिट व्हिस्की की 7488 पेट बोतलें, ऑल सीजन्स गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की की 3840 पेट बोतलें तथा ब्लैक बकार्डी रम की 432 बोतलें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद चोरी–छिपे अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है।

मायावती ने अचानक क्यों रद्द कर दी 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली बड़ी रैली

संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली अपनी बड़ी रैली अचानक रद्द कर दी। यह रैली डॉ. भीमराव आंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में आयोजित होने वाली थी, जिसमें पश्चिमी यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड से लाखों कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद थी। मायावती ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और कहा कि रैली रद्द करने की वजह जनता की सुविधा है। उन्होंने लिखा कि उनके आने पर वीआईपी सुरक्षा और भारी सरकारी इंतजाम किए जाते हैं, जिससे आम लोगों, महिलाओं और बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लंबा इंतजार, भीड़ और धक्का–मुक्की का सामना करना पड़ता है। मायावती ने कहा कि वह अपने कारण किसी भी कार्यकर्ता को परेशानी में नहीं देख सकतीं, इसलिए इस बार वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। मायावती ने कहा कि वह अपने कारण किसी भी कार्यकर्ता को परेशानी में नहीं देख सकतीं, इसलिए इस बार वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, "मेरी वजह मेरे अपने लोगों को तकलीफ हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इस बार मैं खुद नहीं आऊंगी।" उन्होंने कहा, वह लखनऊ स्थित अपने आवास पर ही बाबासाहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगी और कार्यकर्ताओं से भी शांति से, बिना किसी राजनीतिक दिखावे के, श्रद्धांजलि देने की अपील की। रैली रद्द होने की खबर फैलते ही कार्यकर्ताओं में निराशा दिखी। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ से आने के लिए बसें बुक थीं और कई लोग छुट्टी लेकर तैयारी कर चुके थे। लेकिन इसके बाद पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज फैलने लगे कि मायावती ने हमेशा की तरह जनता को प्राथमिकता देकर "बड़ी बहन" होने का परिचय दिया।

रोहिंग्या–बांग्लादेशियों को ढूंढने निकलीं मेयर,सपा पार्षद के प्लॉट पर मिलीं 80 झोपड़ियां

संवाददाता

लखनऊ। सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल खुद ही बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ढूंढने निकलीं। वह गुरुवार को गुडंबा थाना क्षेत्र के फूलबाग बहादुरपुर में नगर निगम की टीम लेकर पहुंच गईं। वहां सपा पार्षद के प्लॉट पर 80 झोपड़ियां मिलीं। मेयर के पहुंचने की भनक लगते ही झोपड़ियों में मौजूद पुरुष भाग गए। वहां केवल महिलाएं बचीं जो उन्हें कोई भी कागज नहीं दिखा सकीं। झोपड़ियों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। अंदर टीवी लगे हैं, फ्रिज भी रखे हैं। मेयर ने कहा– इन झोपड़ियों में बांग्लादेशी रहते हैं। उन्हें 15 दिन का समय दिया है। इन्हें हर हाल में शहर से बाहर जाना होगा। सपा पार्षद के पति पंकज यादव ने कहा झोपड़ियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं रहते हैं। इनमें असम के नागरिक रहते हैं और घरों से कूड़ा उठाकर अपना जीवनयापन करते हैं। लोगों ने बताया ये झोपड़ियां शंकरपुरवा प्रथम वार्ड की सपा पार्षद नमिता यादव के पति पूर्व पार्षद पंकज यादव की जमीन पर बनी हैं। इन झुग्गियों की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। इसकी कई बार मेयर और नगर निगम से शिकायत की थी। मौके पर अवैध तरीके से कूड़ा ढुलाई करने वाली ठेली और कबाड़ बरामद हुआ है। मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा 80 झुग्गियों में बिजली आपूर्ति की जा रही थी। 2 किलो वाट का कनेक्शन लेकर यह खेल चल रहा है। मेयर ने मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा आप लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया सीएम योगी के निर्देश के बाद अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। मैं जब तक पहुंची तब तक पुरुष भाग चुके थे। यहां केवल महिलाएं मिलीं। वे डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा पाईं। झोपड़ियों में मीटर तक लगा रखा है। बिजली विभाग से एसडीओ को साथ लेकर आई थी। उन्हें यहां के सभी कनेक्शन काटने के लिए कहा है। 15 दिन का समय दिया है। ये सब बांग्लादेशी हैं। इन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पूछने पर बताया कि बंप्रेटा गांव के रहने वाले हैं। अपने ग्राम प्रधान, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दे सका। मेयर ने कहा मेरे के साथ अपर नगर आयुक्त ललित कुमार भी पहुंचे। मौके से करीब 50 ठेली बरामद की गई। इन्हें नगर निगम ने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही मौके पर अवैध ढंग से रखा गया। कूड़ा भी नगर निगम की टीम ने जब्त किया है। यहां पर झुग्गियों में सुविधा के भी इंतजाम हैं। इसमें फ्रिज, कूलर भी शामिल है। मेयर सुषमा खर्कवाल ने 15 दिनों में झुग्गी–झोपड़ी खाली करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर तय समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह फिर से 15 दिनों बाद आकर कार्रवाई करेंगी। स्थानीय लोग बोले अवैध तरीके से यह बस्ती बसाई गई। उसके बाद से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का खतरा बना हुआ है। ये लोग कूड़ा–कचरा फैला देते हैं। रात में यहां पर कबाड़ जलाया जाता है। स्थानीय रमेश ने बताया कि पार्षद नमिता यादव के पति पंकज यादव की जमीन पर यह लोग बसे हुए हैं। इन्हीं लोगों की तरफ से इन्हें बसाया गया है। इसके चलते सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद यहां स्थिति बदहाल हो जाती है। गांजा–अफीम सब चलता है। इन लोगों के गंदगी फैलाने के कारण हर मौसम में सबसे पहले हमारे एरिया में डेंगू फैलता है। बस हम यही चाहते हैं कि यहां साफ–सफाई हो जाए। हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। हमें भी खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी जाए। झोपड़ी में रहने वाले इम्तियाज अली ने बताया हम लोग असम के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने दिन में डकैती डाली है। वे लोग लाखों रुपए का सामान लेकर चले गए। इस मौके पर विरोध भी करने लगे। इसके साथ ही एनआरसी सहित अन्य डॉक्यूमेंट भी दिखाने लगे। हम लोग यहीं भारत के रहने वाले हैं। हमारा सामान छोड़ा जाना चाहिए। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो भी घर से कूड़ा या मलबा निकलता है उसका कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नगर निगम करेगा। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पूर्व पार्षद पंकज यादव ने कहा यह हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। मेयर सम्मानित हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि कौन दूसरे राज्य का है, कौन बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। सुषमा खर्कवाल लखनऊ की मेयर हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बांग्लादेशी आ गए? सरकार आपकी है। आप लोग क्या कर रहे हैं? झुग्गी–झोपड़ी में असम के नागरिक रहते हैं। यहां रहने वाले लोगों उन जगहों से कूड़ा उठाते हैं, जहां नगर निगम की गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं। यह लोग ठेली से 50–100 रुपए लेकर कूड़ा उठाते हैं। इसी से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। मेयर के पास में कमीशन कम आ रहा होगा, इसलिए परेशान होंगी। यहां रहने वाले लोग बांग्लादेशी नहीं हैं। यह बात 200 प्रतिशत सही है।

यूपी में 100 विधायकों का बीजेपी काट सकती है टिकट, 2027 को लेकर इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट कार्ड आया सामने

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड़ में है। इसे लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों के कामकाज को लेकर इंटरनल सर्वे कराया है जिससे विधायकों के भविष्य को लेकर पार्टी तय करेगी किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है। अब बीजेपी के इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट कार्ड आया सामने है। पार्टी सूत्रों की मानें तो पूर्वांचल पश्चिम क्षेत्र का सर्वे पहले हुआ जिसमें से काशी,बृज,अवध और अन्य क्षेत्रों का सर्वे शामिल है। पार्टी ने पेशेवर एजेंसियों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। गुप्त सर्वे के जरिए विधायकों की छवि, विकास कार्य, जातीय समीकरण और विपक्ष की ताकत का आकलन किया गया है। भाजपा ने इस सर्वे के पहले चरण को तीन श्रेणी में इसको किया हैपार्टी सूत्रों के अनुसार 'ए' श्रेणी के नेताओं का टिकट लगभग पक्का है,जबकि 'सी' श्रेणी वालों की कुर्सी खतरे में है। विधायकों के ऑडिट के कई पैमाने बनाये गए थे। विधायकों का पिछले कार्यकालों में प्रदर्शन और अपने क्षेत्र में विकास निधि का उपयोग,जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रियता और पिछले चुनाव में जीत का अंतर और उसकी वजह, जनता की नजर में व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि और 2027 में जीत की संभावना इस सर्वे में विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरियों का भी विश्लेषण भी किया गया है। सर्वे में यह दर्ज किया गया कि किस जातीय समूह में किस पार्टी की पकड़ है, कौन–से मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं, और विपक्ष के कौन–से नेता भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। टिकट वितरण में भावनाओं या पुराने रिश्तों को दरकिनार कर प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद भाजपा आलाकमान अब अगले चरण की तरफ बढ़ेगा।अब अगले चरण में बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए संगठनात्मक जिलों से पैनल तैयार कराएगी। जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद मिलकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन–तीन संभावित उम्मीदवार का पैनल तैयार करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे। वह पैनल प्रदेश कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा। कोर कमेटी प्रत्येक जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ पैनल में नामित नामों से नाम तय करेगी। कोर कमेटी बीजेपी को हिस्से वाली सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष पेश करेगी। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश से मिली सूची, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सर्वे में आए नामों के आधार पर एक कॉमन पैनल तैयार करेंगे। उस पैनल पर लंबी चर्चा, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय संतुलन देखते हुए प्रत्याशी तय किए जाएंगे। यूपी में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही भाजपा विधायकों के विधानसभा टिकट को लेकर पैनल का फार्मूला भी अपनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार -मुख्यमंत्री साय

पीएम आवास के 1073 हितग्राहियों को नये आवास की चाबी सौंपी
सुहेला में 195 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195.26 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत पाँच हजार किसानों को अधिकार अभिलेख तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ध्येय है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए हमारी सरकार जनता के हित में वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बने 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में जो वादे किए गए थे, उन्हें हम एक–एक कर पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये कर दी गई है। किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस भी प्रदान किया जा चुका है। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी मिल रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने घरों में सोलर पैनल स्थापित कर लाभ उठाएँ। उन्होंने जिले में प्रशासन की 'हम होंगे कामयाब' पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे अब तक 500 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है और बड़े–बड़े कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार –भाटापारा जिले में अकेले 100 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कों की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम के दौरान सुहेला में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, तिल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, बलौदाबाजार में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन एवं नवीन व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने जिले के 50 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए 10–10 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण तथा सुहेला तिगड्डे में तीनों सड़कों पर एक–एक किलोमीटर तक डिवाइडर निर्माण एवं लाइट लगाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 12.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1073 आवास, तथा लगभग 7.74 करोड़ रुपये की लागत से आमाकोनी, हथबंद, पोसरी, सेम्हराडीह और खपराडीह में निर्मित जल प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं। भूमिपूजन के प्रमुख कार्यों में 49.17 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार–रिसदा–हथबंद मार्ग मजबूतीकरण, 20.98 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार के रिसदा बायपास मार्ग, 15.59 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, 8.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 717 आवास तथा 8.04 करोड़ रुपये की लागत से कोल्हान नाले के पार सुंगेरा एनिकट निर्माण शामिल हैं। कार्यक्रम में 5 करोड़ रुपये से अधिक की हितग्राहीमूलक सामग्री एवं चेक वितरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से सायबर फ्रॉड प्रकरण के 27 लाख रुपये की वापसी, श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में 83 लाख रुपये का वितरण, 8333 छात्रों को 4.25 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, महिला स्व सहायता समूहों एवं 'सक्षम' योजना अंतर्गत 16 महिलाओं को 25 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 हितग्राहियों को 9.69 लाख रुपये तथा 'हम होंगे कामयाब' योजना अंतर्गत 60 हितग्राहियों को 6.81 लाख रुपये का भुगतान शामिल है। इस अवसर पर बलौदाबाजार–भाटापारा जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर नवीन अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा, जनपद अध्यक्ष सिमगा दौलत पाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

एनसीएल अंतरक्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025-26 निगाही परियोजना में हुई सम्पन्न

बीएनई

सिंगरौली। बुधवार को एनसीएल की निगाही परियोजना में अंतरक्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025–26 सम्पन्न हुई। 2 से 3 दिसम्बर, 2025 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में एनसीएल की सभी परियोजना एवं इकाइयों से कुल 564 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंतरक्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025–26 के दौरान पुरुष एवं महिला वर्ग में विभिन्न श्रेणियों जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर दौड़, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जेवलीन थ्रो, हैमर थ्रो, हाइ जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, रिले रेस, तीरंदाजी, पिचर रेस, साईकिल रेस एवं पोल वौल्ट में मैच खेले गए। समापन समारोह के दौरान महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) राजेश त्रिवेदी बतौर मुख्य अतिथि एवं श्रमिक संघ से जेसीसी सदस्य–सीएमएस से अजय कुमार यादव, आरसीएसएस से लाल पुष्पराज सिंह, बीएमएस से अशोक कुमार मिश्रा, एचएमएस से अशोक कुमार पांडे, सीएमओएआई प्रतिनिधि सर्वेश सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं महाप्रबन्धक (विद्युत एवं यान्त्रिकी), निगाही रणधीर सिंह, एनसीएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड मेम्बर्स, परियोजना जेसीसी सदस्य, विभागाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। अमलोरी टीम रही विजेता इस प्रतिस्पर्धा के दौरान ओवरऑल चौंपियनशिप में अमलोरी टीम विजेता एवं सीडबल्यूएस और जयंत की टीम उपविजेता रहे। इंडिविजुअल चौंपियनशिप में पुरुष वर्ग में यश वर्मा (ब्लॉक–बी) विजेता, दुलाराम (सीडबल्यूएस) उपविजेता तथा महिला वर्ग में इन्दु बाला (मुख्यालय) विजेता तथा तृप्ति पुरी (अमलोरी) ने उपविजेता खिताब अपने नाम किया। गौरतलब है कि एनसीएल द्वारा प्रतिवर्ष अपने कर्मियों का मनोबल बढ़ाने एवं उनके शारीरिक और मानसिक विकास हेतु ऐसी अनेक खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है।

53 शतक और 34 वेन्यू, भारत नहीं, कोहली ने श्रीलंका-बांग्लादेश के इन शहरों में लगाए सर्वाधिक सैकड़े

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कोहली फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में शतक लगा चुके हैं। 2027 वनडे विश्व कप में खेलने के लिए प्रयासरत कोहली ने लगातार दो शतक लगाकर साबित कर दिया है उनके अंदर रन बनाने की भूख अभी भी बाकी है। कोहली अब तक वनडे में 53 शतक लगा चुके हैं और वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी एक प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। रायपुर में दिखा कोहली का पुराना अंदाज कोहली अपने पुराने रंग में नजर आ रहे हैं। कोहली ने इससे पहले रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी और फिर रायपुर में भी उन्होंने इस फॉर्म में जारी रखते हुए शतक लगाया। कोहली का यह वनडे में 53वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 84वां शतक है। कोहली वनडे में शतक लगाने के मामले में सभी से काफी आगे निकल गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है जिन्होंने 100 शतक लगाए हैं। कोहली दूसरे मैच में 93 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 रन बनाकर आउट हुए। सबसे आगे निकले कोहली कोहली ने 11वीं बार वनडे में लगातार दो शतक लगाए हैं और वह इस मामले में सभी से काफी आगे हैं। भारत ही क्या अन्य कोई भी देश का बल्लेबाज इस मामले में उनके करीब भी नहीं है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने वनडे में छह बार लगातार दो शतक लगाए हैं। कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह वनडे में लगातार तीसरा शतक है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 में नाबाद 101 रन बनाए थे। इसके बाद रांची में 135 रन और अब 102 रनों की पारी खेली। सचिन की बराबरी पर पहुंचे विराट कोहली ने वनडे में 34 वेन्यू पर शतक लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। सचिन ने भी वनडे में 34 अलग–अलग स्थानों पर शतक जड़े हैं जो किसी बल्लेबाज द्वारा इस प्रारूप में सर्वाधिक है। अब कोहली भी उनके साथ इस सूची में शीर्ष पर काबिज हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोहली ने भारत नहीं, बांग्लादेश और श्रीलंका के दो शहरों में सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं। दुनिया के किन स्थानों पर कोहली ने जड़े शतक कोहली के 53 वनडे शतक दुनिया के 34 वेन्यू पर आए हैं।

संक्षिप्त

भारत की तेज बढ़ती आर्थिक रफ्तार ग्लोबल पावरशिफ्ट की शुरुआत, पश्चिमी मीडिया ने कहा- यह कृत्रिम नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ को बेअसर करते हुए दूसरी तिमाही में भारतीय जीडीपी की 8.2% वृद्धि, विनिर्माण व सेवाओं में उछाल व घरेलू मांग की मजबूती ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर मोड़ दिया है। पश्चिमी और खाड़ी देशों के मीडिया समूहों ने इसे ग्लोबल पावरशिफ्ट की शुरुआत बताया है, जहां अमेरिका–चीन की धीमी आर्थिक रफ्तार के बीच भारत सबसे तेजी से उभरती शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। यह तेज भागती आर्थिक रफ्तार कृत्रिम नहीं बल्कि लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम है। अमेरिकी मीडिया ग्रुप्स ने लिखा, भारत की वृद्धि दर लगातार 6 तिमाहियों तक 7 प्रतिशत से अधिक रहना विश्व अर्थव्यवस्था में दुर्लभ है।

एआई क्षमता बढ़ाने पर जोर, विदेशी निर्भरता कम होगी, भारतीय डाटा की सुरक्षा भी मजबूत होगी

एजेंसी

मुंबई। भारत को तत्काल अपनी सॉवरेन एआई क्षमताएं विकसित करनी होंगी। नहीं तो देश को विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ेगा। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा, यह विदेशी कंपनियां अपने एआई मॉडल को मजबूत करने के लिए भारतीय डाटा का इस्तेमाल कर रही हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में कांत ने कहा, देश की तकनीकी प्रगति इस बात से परिभाषित होगी कि वह इस समय कितनी तेजी से घरेलू कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करता है। संवेदनशील डाटा की सुरक्षा करता है और साथ ही स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिस्टम बनाने वाले स्टार्टअप्स का समर्थन करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बड़े पैमाने पर समावेशन को बढ़ावा दिया है, लेकिन देश की पिछड़ी कंप्यूटिंग क्षमता इसकी प्रगति को धीमा करने का खतरा पैदा कर रही है। अमिताभ कांत ने ओपनएआई और एनवीडिया के बीच हाल ही में हुई साझेदारी का हवाला देते हुए कहा, इस प्रयास से 10 गीगावॉट की जीपीयू क्षमता तैयार होगी, जो लगभग 50 लाख हाई–परफॉरमिंग प्रोसेसर के बराबर है, जबकि भारत में लगभग 30,000 जीपीयू ही हैं। इस अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है।

मोदी-पुतिन दोस्ती में आगे, व्यापार में पीछे, 100 बिलियन डॉलर तक कैसे पहुंचेगा व्यापार

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के श्ऑल वेदर फ्रेंडश बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच इन संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। लेकिन मुख्य रूप से दोनों गहरे दोस्तों के बीच यह दोस्ती रूसी सैन्य उपकरणों की खरीद तक सिमटी हुई है। इसका लाभ भी एक तरफा रूस को ही मिलता रहा है। जबकि अमेरिका और यूरोप रूस के साथ तमाम विवादों के बाद भी उसके बड़े व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। भारत और रूस की इस दोस्ती को और गहरा करने के लिए दोनों ही देशों ने अपने बीच होने वाले व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन यह लक्ष्य कैसे हासिल होगा और इसका लाभ किसे मिलेगा? दोनों देशों के बीच इस समय करीब 63.6 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। लेकिन दोनों ही देशों के नेता इस बात के लिए उत्सुक हैं कि यह व्यापार अगले पांच वर्षों में 100 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इंडियन–रसियन बिजनेस फोरम के मंच पर जब रूसी पुतिन भाग लेंगे, तब यह उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इस समय रूस–भारत के बीच तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद सबसे बड़ी व्यापारिक हिस्सेदारी है। भारत की ओर से रूस में करीब 16 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है, इसका ज्यादातर हिस्सा पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में है। इसी तरह रूस का भारत में करीब 20 बिलियन डॉलर का निवेश है। इसका अधिकतर हिस्सा पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक भागीदारी बढ़ाने की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। रूस भारत को नवीनतम युद्ध तकनीक से लैस सुरक्षा उपकरणों, लड़ाकू विमानों के निर्माण में सहायता कर सकता है। इसे पारस्परिक व्यापारिक अवसरों की तरह तब्दील किया जा सकता है। फाइटर पायलट रहित विमान और ड्रोन से हमला नई सामरिक आवश्यकता बनकर उभरी है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए भारत को इस तकनीक में पारंगत होना होगा। रूस इसमें भारत की बड़ी सहायता कर सकता है। खाद्य उत्पादों–सेवाओं को खरीदने पर समझौता करेगा रूस वहीं, भारत प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, फल–सब्जी, सॉफ्टवेयर बाजार, वस्त्र–आभूषण, फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में मजबूत है। इन सेक्टर की सेवाओं, उत्पादों को रूस को बेचकर भारत एक बेहतर बाजार हासिल कर सकता है। भारत ने डिजिटल सेवाओं को उपलब्ध कराने के मामले में नया कौशल हासिल किया है। रूसी राष्ट्रपति ने इस तकनीक और अनुभव को भारत से हासिल करने में रुचि जताई है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस भारतीय खाद्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर एक समझौता कर सकता है। भारत जैसा मजबूत व्यापारिक साझेदार नहीं खोना चाहेगा रूस आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉ. नागेंद्र कुमार शर्मा ने अमर उजाला से कहा कि अब तक हमारी भागीदारी सैन्य आवश्यकताओं और पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित रही है। लेकिन अब इसे दूसरे हिस्सों तक बढ़ाने की आवश्यकता है। रूस से तेल व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी जिस तरह भारत ने रूस से तेल खरीदा है, उसने रूस को यह भरोसा दिला दिया है कि भारत अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के दबाव के बाद भी झुकेगा नहीं। स्वयं रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना इसकी प्रशंसा की है। रूस अभी भी युद्ध में उलझा हुआ है। अमेरिका और यूरोप जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में रूस की परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उस स्थिति में भी रूस चाहेगा कि उसके पास भारत जैसा मजबूत दोस्त हो जो उसके साथ युद्ध में भले न उतरे, लेकिन वह तेल खरीद कर उसे आर्थिक मजबूती देता रहे। रूस की इस आवश्यकता को भारत अपने घरेलू बाजार में तेल कीमतों को स्थिर रखने में उपयोग कर सकता है। रूस के पास प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। वह आज भी यूरोप को सबसे अधिक गैस की सप्लाई करता है। भारत में जिस तरह ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकारें जिस तरह गैस आधारित वाहनों–उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं, भारत में प्राकृतिक गैस की मांग में लगातार बढ़ोतरी होने वाली है। रूस इसमें भारत की बड़ी मदद कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार एंटन कोब्याकोव ने कहा है कि भारत पिछले पांच वर्षों से रूस का दूसरा सबसे मजबूत व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में लगभग सात गुने तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि रूस से भारत को बेचे गए तेल के कारण आई है। लेकिन इस व्यापारिक साझीदारी को मजबूत करने और इसे स्थायित्व देने के लिए नए उपायों की तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस अपने ऐसे मजबूत व्यापारिक साझीदार को कभी नहीं खोना चाहेगा जो अमेरिका जैसे मजबूत देश के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भी उसके साथ व्यापार कर सके। भारत को इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और अपना व्यापार बढ़ाने के अवसर तलाशना चाहिए। बाजार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे डॉ. नागेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अब इस दोस्ती को नई ऊंचाई दी जानी चाहिए। भारत ने निर्माण को अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत बना रखी है। और इसमें स्टील और सीमेंट सबसे बड़ी आवश्यकता होते हैं। रूस इस सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी है। पुतिन अपने इस दौरे में इस सेक्टर से जुड़ा समझौता करते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की जानकारी सामने आई है, रूस भारत से खाद्य उत्पादों और सेवाओं की खरीद पर समझौता कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो इससे भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा और भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

दिन में स्कूल, रात में बैग की जगह अंडे का लगाया ठेला, अब निकुंज हुए नेशनल थ्रो बॉल में चयनित

एजेंसी

अलीगढ़। अलीगढ़ के जट्टारी निवासी कक्षा छह का छात्र निकुंज उन बच्चों में है, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी निभाते हैं। वह दिन में स्कूल जाता है और रात में अंडे का ठेला लगाता है। खेल के प्रति लगन से उसका चयन नेशनल थ्रो बॉल के लिए हुआ है, यह प्रतियोगिता 26 से 28 दिसंबर तक स्कॉलर पब्लिक स्कूल वाराणसी में आयोजित होगी। बचपन में ही पिता साथ छोड़कर चले गए तो घर की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। मां ने लोगों के घरों में घरेलू सहायिका बनकर चार बच्चों को पाला। इन्हीं चार बच्चों में सबसे छोटा है निकुंज। दिन में वह स्कूल जाता है, लेकिन रात होते ही उसकी जिंदगी बदल जाती है। स्कूल बैग की जगह वह अंडे का ठेला संभालता है। ठंड, गर्मी, बरसात–कुछ भी हो, वह रोज ठेला लगाता है ताकि अपनी स्कूल फीस भर सके और घर का खर्च उठा सके। इतनी छोटी उम्र में उसका हौसला और मेहनत बड़े–बड़ों को भी मात देता है।इसी संघर्ष के बीच उसने खेल में अपना हुनर पहचाना और थ्रो बॉल खेलने लगा। हरसुख सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी की सचिव जीनत अली ने बताया कि वह एसडी पब्लिक स्कूल जट्टारी में कक्षा छह का छात्र है और एक होनहार खिलाड़ी है। इसलिए वह उसे निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं। मेहनत और प्रतिभा ने उसके सपनों को एक नई उड़ान दी है। नेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ है। उसका चयन न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है। उसकी कहानी बताती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों तो भी हौसला और मेहनत रास्ता बना ही लेते हैं।

विजय देवरकोंडा से शादी की चर्चाओं पर रश्मिका मंदाना ने दी प्रतिक्रिया, जवाब सुन फैंस हुए उत्साहित

एजेंसी

पिछले कुछ वक्त से रश्मिका मंदाना काम से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बनी हैं। ये चर्चाएं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर हो रही हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रश्मिका और विजय अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि, रश्मिका या विजय ने अब तक इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। अब रश्मिका ने अपनी शादी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, एक्ट्रेस ने पूरी तरह से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। रश्मिका ने बताया कब करेंगी कंफर्म हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत के दौरान रश्मिका ने अपनी आगामी फिल्मों और वर्कफ्रंट के साथ–साथ अपनी शादी की चर्चाओं पर रिएक्ट किया। इस दौरान जब रश्मिका से पूछा गया कि क्या वह विजय से अपनी कथित शादी की पुष्टि या खंडन करना चाहती हैं? तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मैं शादी की पुष्टि या खंडन नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहूंगी कि जब इस बारे में बात करने का समय आएगा, तब हम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने फैंस या मीडिया के साथ कुछ भी साझा करने से पहले थोड़ा समय लेना चाहती हैं। रश्मिका की इस प्रतिक्रिया के बाद दोनों की शादी को लेकर अटकलें और भी तेज हो गई हैं। फरवरी में शादी करने की हैं चर्चाएं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दोनों की शादी उदयपुर में होगी। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि रश्मिका शादी की तैयारियों के लिए उदयपुर में इंतजाम तक देखने जा चुकी हैं। अक्तूबर में विजय–रश्मिका ने की थी सगाई रश्मिका और विजय की सगाई की खबरें अक्तूबर में काफी चर्चा में रही थीं। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इन्हें स्वीकार या खारिज नहीं किया और न ही कोई फोटोज सामने आई।

नए व्यवसायों की संख्या बढ़ने से सेवा क्षेत्र में तेजी, नवंबर में वृद्धि रही जोरदार

एजेंसी

नई दिल्ली। नए व्यवसायों की संख्या में तेजी से वृद्धि और कीमतों में कमी से नवंबर में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आई है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स बढ़कर 59.8 हो गया। अक्तूबर में यह गिरकर 58.9 पर आ गया था। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में, 50 से ऊपर का मतलब मजबूती और इससे नीचे का मतलब कमजोरी माना जाता है। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, नए व्यवसायों के आने से सेवा क्षेत्र के उत्पादन वृद्धि को बढ़ावा मिला है। एशिया, यूरोप व मध्य पूर्व में कंपनियों के लाभ दर्ज करने के साथ अंतरराष्ट्रीय बिक्री में सुधार जारी रहा। हालांकि, विस्तार की दर आठ माह के निचले स्तर पर आ गई।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743